

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 132] | नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2016/वैशाख 13, 1938     |
|----------|---|
| No. 132] | NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/VAISAKHA 13, 1938 |

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

# जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नॉमिनल रिम डाया कोड वाले ट्यूब सहित अथवा ट्यूब रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक रेडियल टायरों और/अथवा रबड़ के फ्लैप (बिना ट्यूब वाले टायरों सहित)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/14 /2015-डीजीएडी.— आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे ए टी एम ए अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमवली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है), के अनुसार घरेलू उत्पादकों नामत: अपोलो टायर्स लि0, जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि. और सिएट लि. की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे संबद्ध देश भी कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नॉमिनल रिम डाया कोड वाले ट्यूब सहित अथवा बिना ट्यूब वाले नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक रेडियल टायरों और/अथवा रबड़ के फ्लैप (बिना ट्यूब वाले टायरों सहित)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

2199 GI/2016 (1)

2. और अतः प्राधिकारी प्रथमदृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षित तथा कथित पाटन एवं क्षित के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षित की पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं तािक कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क उस रािश की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षित को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### विचाराधीन उत्पाद

- 3. वर्तमान जांचों में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त 16" से अधिक नॉमिनल रिम डाया कोड वाले ट्यूब सहित अथवा ट्यूब रहित नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक रेडियल टायर और/अथवा रबड़ के फ्लैप हैं।
- 4. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 40112010 के तहत अध्याय 40 में वर्गीकृत किया जाता है और ट्यूब एवं फ्लैपों जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के क्रमश: शीर्ष सं. 40131020 तथा 40129049 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक रेडियल टायरों के बिना आयातित ट्यूबों और/अथवा फ्लैप विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह जांच के कार्यक्षेत्र में बाध्यकारी नहीं है।

## समान वस्तु:

5. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से भारत में पाटित की गई संबद्ध वस्तुओं के समान हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आवेदनकर्ताओं के द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के अनुसार कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के लिए भारत में याचिकाकर्ता के द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के ''समान वस्त्" माना जा रहा है।

# घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

6. आटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के द्वारा घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदन दायर किया गया है। इन घरेलू उद्योगों में अपोलो टायर्स लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि. और सिएट लि. शिमल हैं। आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार संघटक घरेलू उत्पादकों के उत्पादन से संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन के बृहद अनुपात बनता है। इसके अलावा, संघटक घरेलू उत्पादकों ने यह घोषणा की है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश के विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक से संबंधित हैं अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातकर्ता से संबंधित नहीं है। अत: प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि वर्तमान आवेदन में संघटक घरेलू उत्पादकों, नामत: अपोलो टायर्स लि., जे.के. टायर इंडस्ट्रीज लि. और सिएट लि. नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं तथा संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंड को आवेदन में पूरा किया जाता है।

## संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है। याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए डी जी सी आई एंड एस के अनुसार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान और स्पेन से संबद्ध वस्तुओं के आयात, चीन जन.गण. के आयातों के अलावा, न्यूनतम स्तर से भी अधिक हैं। तथापि, याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार जापान और स्पेन की औसत कीमत चीन की कीमत से काफी अधिक हैं। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त न्यूनतम होने के बावजूद, जापान और

स्पेन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से याचिकाकर्ता उद्योगों को क्षति नहीं हो रही है। इसलिए, जापान और स्पेन संबद्ध देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

## सामान्य मूल्य

8. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए। याचिकाकर्त ने विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी अनुमान तथा चीन जनवादी गणराज्य के प्रक्रिया दिखाने वाले निर्यातकों द्वारा इसका खण्डन करने के अध्यधीन चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार अनुमान लगाया गया है।

## निर्यात कीमत:

9. याचिकाकर्ता ने डी जी सी आई एंड एस के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, रखरखाव प्रभार, अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री बीमा और वैट के संबंध में कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं।

## पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य की कारखानागत निर्यात कीमत से तुलना की गई है। इस बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य कीमत कारखानागत निर्यात कीमत से अधिक है जो यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों के द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं को पाटित किया जा रहा है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक होने का अनुमान है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने समग्र रुप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के तौर पर कथित पाटन के परिणामस्वरुप और भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में क्षित होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आवेदक ने घरेलू उद्योग को भारी क्षित होने की संभावना का भी दावा किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षित के आकलन के लिए विचार किया गया है। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही है। परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत में कमी होने से आयातों के बाजार हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में प्रतिस्थापन क्षेत्र में धीरे-धीरे कमी आयी है। घरेलू उद्योग की समान सूचियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के द्वारा उठायी जा रही क्षित के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

## जांच अवधि

12. याचिकाकर्ता ने 2012-13, 2013-14, 2014-15 के रूप में क्षित अवधि और प्रस्तावित जांच अवधि सिहत जुलाई, 2014-जून, 2015 (12 महीनों) के रूप में जांच अवधि (पीओआई) का प्रस्ताव किया। तथापि, अधिक अद्यतन आंकड़ों के आधार पर अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी एतद्वारा जांच अवधि जुलाई, 2014-दिसम्बर, 2015 (18 महीनों) के रूप में निर्धारित करते हैं। तथापि, क्षित जांच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच अवधि की अवधियां शामिल होंगी।

## सूचना प्रस्तत करना

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जिरए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्रधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

## समय-सीमा

- 15. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
- 16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र में अपनी अन्य टिप्पणियां और सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें। सूचना गोपनीय आधार पर दें।

# गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

- 17. प्रश्नावली के उत्तरों/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के मामले में इस दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए।
- 18. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी के द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा गोपनीय वृतांतों की 2-2 प्रतियां और अगोपनीय वृतांतों की 5-5 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।
- 19. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है और/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।
- 20. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की

विषय वस्तु के समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, विषय परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आशय के कारणों का एक विवरण उपलबध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

- 21. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 22. सार्थक गोपनीयता रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

## सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजिनक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रख्ने गए हैं।

## असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अविध के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है अथवा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> May, 2016

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "New/unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres) having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks", originating in or exported from China PR.

No. 14/14/2015-DGAD.—Automotive Tyre Manufacturers' Association (hereinafter referred to as ATMA or the petitioner) has filed an application on behalf of the domestic producers namely Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd. and Ceat Ltd., before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the imports of "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap of rubber (including tubeless tyres), having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. AND WHEREAS, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, and injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence,

degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

### **Product under consideration**

- 3. The product under consideration (PUC) in the present investigations is "New/Unused pneumatic radial tyres with or without tubes and/or flap, of rubber, having nominal rim dia code above 16" used in buses and lorries/trucks".
- 4. The PUC is classified in Chapter 40 under customs subheading No. 40112010 and tubes and flaps are classified under 40131020 and 40129049 respectively of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. Tubes and or flaps imported without New/Unused pneumatic radial tyres are outside the scope of the PUC. The Custom classification, however, is indicative only and not binding on the scope of investigation.

### Like Article

5. The petitioner has claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are identical to the subject goods being dumped into India from the subject country. The petitioner has claimed that the subject goods produced by the applicants and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

### **Domestic Industry & Standing**

6. The application has been filed by Automotive Tyre Manufacturers' Association, on behalf of the domestic producers comprising of Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd. and Ceat Ltd. As per information furnished in the application, the production of the constituent domestic producers accounts for major proportion of the total domestic production of the subject goods. Further, the constituent domestic producers have declared that they have neither imported the product under consideration from the subject country, nor are they related to any exporter of the product under consideration in the subject country or to an importer of subject goods in India. The Authority, therefore, determines that the constituent domestic producers in the present application namely Apollo Tyres Ltd., J. K. Tyre Industries Ltd. and Ceat Ltd constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

### **Subject Country**

7. The subject country in the present investigation is China PR. As per the DGCI&S data furnished by the petitioner, the Authority notes that apart from China PR, imports of subject goods from Japan and Spain are also above de minimis level. However, as claimed by the petitioner, the average price from Japan and Spain are much higher than that of China. Consequently, despite being above de minimis, the imports of subject goods from Japan and Spain are not causing injury to the petitioner industries. Therefore, Japan and Spain are beyond the purview of the subject country.

### **Normal Value**

8. The applicants have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules.

#### **Export Price**

The petitioner has determined the export price by adopting DGCI&S data. Price adjustments have been made on account of commission, port expenses, bank charges, handling charges, inland freight, ocean freight, marine insurance and VAT.

### **Dumping Margin**

10. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

### Injury and Causal Link

11. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The applicant has also claimed threat of material injury to the domestic industry. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. Dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the volume of imports has increased significantly. Price undercutting being caused by the dumped imports is resulting in increase in market share of imports and decline in market share of the domestic industry. Further, the market share of the domestic industry has steeply declined in the replacement segment. The inventories with the domestic industry have increased significantly. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

### **Period of Investigation**

12. The petitioner proposed the period of investigation (POI) as July 2014- June 2015 (12 Months) with the injury period as 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the proposed POI. However, for making required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as July 2014-December, 2015 (18 Months) The injury investigation period will however cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI.

#### Submission of Information.

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevantara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

#### **Time Limit**

- 15. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.
- 16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation. Submission of information on confidential basis

### SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other

set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

- 18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
- 19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
- 20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to 7 permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information. Inspection of public file

### INSPECTION OF PUBLIC FILE

23. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

### Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority